आयोग के मुआवज़े के निर्देशों की सरकार कर रही अनदेखी

हर्जाने के 21 में से केवल 3 मामलों पर किया गया अमल

Krishna.Shukla@timesgroup.com

■ मुंबई : मानवाधिकार आयोग एक कुशल प्रहरी की तरह मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन आयोग के मुआवजे आदेशों के प्रति सरकार की बेरुखी साफ झलकती है। जनवरी, 2023 से अब तक आयोग ने सरकार के पास मुआवजे के 21 निर्देश भेजे, मगर इनमें से केवल 3 आदेशों में मुआवजा दिया गया है। अविलंब स्वतः सक्रिय होने वाले आयोग ने यह आदेश अलग-अलग केसों में दिए थे। इन आदेशों मुआवजे की रकम 25 से 30 लाख रुपये के बीच होगी। इसके बावजूद मुआवजे के आदेशों को उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

'आदेश की अवमानना का खौफ नहीं': आयोग इन सभी कारणों की पड़ताल करता है। जो मानवीय गरिमा को घटाते हैं अथवा ठेस पहुंचाते हैं। फिर मामला पुलिस की सर्वरता का हो या प्रशासकीय निष्क्रियता का। आयोग सब की खबर लेता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार आयोग के आदेश के प्रति बेखबर नजर आती है। खासतौर से मुआवजे के आदेश को लेकर। यह आदेश हिरासत में आरोपी के प्रति पुलिस की मनमानी, बदसलूकी, खुनियादी सुविधाओं को लेकर स्थानीय निकायों की लापरवाही, मानवाधिकारों के उल्लंघन, मेडिकल नेग्लिजेंस, जरूरी कानूनी कार्रवाई न करने के लिए जारी किए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स रेग्युलेशन के प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे के आदेश दिए जाते हैं। यह आदेश जारी होने के बाद आयोग के प्रशासन की ओर से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाता है। पत्र पर जब कोई हरकत नहीं होती, तो दोबारा 6 माह के अंतराल पर स्मरण पत्र भेजा जाता है।

सूत्रों के अनुसार कई लोगों को सालों बाद मुआवजा मिलता है। नियमानुसार, यदि सरकार को आयोग के आदेश पसंद नहीं होता है, तो उसके पास बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार होता है, मगर सरकार इस अधिकार का इस्तेमाल करने की बजाय चुप चाप बैठी रहती है। नतीजा मुआवजे का आदेश केवल कागज में सिमटा रहता है। आयोग के मुआवजे के आदेश पर शीघ्रता से अमल न होने की बड़ी वजह यह है कि यह आदेश बाध्यकारी न होकर सिफारिश होता है। लिहाजा अधिकारियों को आदेश की अवमानना का कोई भय नहीं होता है। यह मुआवजा के अमल को लेकर सुस्ती की बड़ी वजह है, जो आयोग के हित में नजर नहीं आती।

रिक्त पद बड़ी चुनौती: आयोग के लिए यहां के स्टॉफ के रिक्त पद बड़ी चुनौती है। आयोग के लिए 54 पद मंजूर किए गए है। इनमें से 50 प्रतिशत पद रिक्त है। यहां पर तैनात ज्यादा तर कर्मचारी ठेके पर आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त किए गए है। पदों के रिक्त होने का असर आयोग के कामकाज पर पड़ रहा है। आयोग प्रभावी ढंग से लोगों को रोजगार दे सके। इसके लिए उसे सभी सुविधाएं और संसाधन देना जरूरी है।

"यदि मुआवजे की रकम पीड़ित शख्स को आयोग के कार्यालय में मिल जाए, तो यह बहुत अच्छा होगा। कमजोर तबके के लोग आयोग में परेशानी लेकर आते हैं। मुआवजे के लिए उनसे मंत्रालय के चक्कर काटने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हर्जाने की रकम पर सरकार की निष्क्रियता आयोग के रुतबे और प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। यह आयोग की साख को धक्का पहुंचाता है। यदि सरकार को आयोग का आदेश पसंद नहीं है, तो उस पर चुपचाप बैठे रहना उससे अपेक्षित नहीं है। सरकार या तो आयोग के आदेश को स्वीकार करे या फिर उसे चुनौती दी। -ऐडवोकेट सिद्ध विद्या, मानवाधिकारों की विशेषज्ञ

सामना

प्राण्यांचे संगोपन महत्त्वाचे!

उच्च न्यायालयाने सिडकोला सुनावले पनवेलमधील गोशाळा रिकामी करण्याच्या खटाटोपाला लगाम

मुंबई, दि. २९ (प्रतिनिधी)– प्राण्यांचे हित जोपासणे, त्यांचे योग्य प्रकारे संगोपन होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भटक्या प्राण्यांच्या संगोपनासाठी काही स्वयंसेवी संस्था निस्वार्थी भावनेने काम करताहेत. त्यांच्या सेवेमध्ये खो घालू नका, प्राण्यांची फरफट होऊ देऊ नका, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सिडकोला सुनावले. याच वेळी पनवेलच्या आसुडगाव गोशाळेतील प्राण्यांना अन्यत्र स्थलांतरित करून संबंधित गोशाळा रिकामी करण्याच्या सिडकोच्या खटाटोपाला लगाम लावला.

आसुडगाव गोशाळेत प्राण्यांचा सांभाळ करणाऱ्या गोवंश रक्षण संवर्धन संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी संस्थेतर्फे ॲड. हरीश पंड्या, ॲड. सिद्ध विद्या व ॲड. शलाका कारकर यांनी बाजू मांडली. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पबाधित गावांतील प्राणी, मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघातात जखमी होणारे प्राणी, भटके प्राणी तसेच पोलिसांच्या कारवाईत जप्त केलेल्या प्राण्यांचे आसुडगाव गोशाळेत सेवाभावी वृत्तीने संगोपन केले जाते. सिडकोने 'डॉग शेल्टर'च्या नावाखाली येथील प्राण्यांना पुण्यात स्थलांतरित करण्याचा घाट घातला आहे. सिडकोची ही कृती प्राण्यांच्या जीविताला धोका पोचवणारी आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि आसूडगाव येथील गोशाळा रिकामी करण्याच्या अनुषंगाने सिडकोने सुरू केलेल्या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती दिली.

सिडकोसह केंद्र सरकार, राज्य गृह विभागाला नोटीस

आसुडगावच्या गोशाळेत तब्बल ५००हून अधिक प्राण्यांचा सांभाळ केला जात आहे. येथील प्राण्यांना अन्यत्र हलवू नये, आम्ही प्राण्यांची फरफट होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेत न्यायालयाने सिडकोसह केंद्र सरकार, राज्याचा गृह विभाग, महसूल व वन विभाग, राष्ट्रीय प्राणीकल्याण केंद्र आदी प्रतिवादींना नोटीस बजावली. प्रतिवादींनी संस्थेच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आणि पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला निश्चित केली.

■ सिडकोने आपल्या कार्यक्षेत्रात प्राण्यांच्या संगोपनासाठी किती पशुसंवर्धन केंद्रे व पशुवैद्यकीय रुग्णालये कार्यरत आहेत, याचा आढावा घेतला पाहिजे. यासंदर्भात न्यायालयाने सिडकोला निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्या संस्थेने न्यायालयाला केली.

Scanned with OKEN Scanner